tribution system or need to supplement the same. In view of the strain on the public distribution system in the context of reduced stocks, the system of licensed retailers has helped to improve availability in the open market. However, it has come to notice of Government that in some cases the merchants have not fully co-operated in the matter. Government will continue to review the position from time to time in the light of the experience and prevailing situation.

Procurement and distribution price of foodgrains

*4. SHRI P. NARASIMHA REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what changes in procurement prices and policies and improvements in distribution costs and arrangements in respect of foodgrains have been effected to ensure adequate availability at fair prices; and

(b) whether the issue price of foodgrains cannot be lowered by effecting economies in handling and overhead costs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b). The procurement prices for kharif and support prices for rabi foodgrains have been revised upwards to ensure adequate incentive to farmers and for maximising procurement for distribution through public agencies. The question of effecting economy in the cost of distribution is constantly under review of the Government.

Family Planning Programme

*5. SHRI K. KODANDA RAMI REDDY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether the present approach of Family Planning Programme is not successful;

(b) whether the Centre is contemplating to introduce certain practical measures to modify the present approach; and

(c) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. KARAN SINGH): (a) to (c). Family Planning efforts are being further intensified and an integrated approach of providing Health, Maternity and Child Care, Nutrition and Family Planning Services is being attempted. Efforts will be made for greater community involvement in the programme. It is also proposed to intensify the programme in districts that had shown high growth rate and density of population.

चावल के व्यापार का सरकारीकरण

*6. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री पी० एम० महता

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष खरीफ की फसल तैयार हो जाने पर चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के निर्णय को बदल दिया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने जनता को उचित मूल्य पर चावल तथा अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जो योजना तैयार की है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) भारी अधिप्राप्ति से बनाए गए केन्द्रीय पूल से इस समय राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों का आवंटन

किया जाता है और यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे केन्द्र द्वारा आवंटित खाद्यान्नों और स्थानीय अधिप्राप्ति से उपलब्ध खाद्यान्नों का वितरण सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर उचित मूल्य की दुकानों / राशन की दुकानों के माध्यम से करें। मौजूदा प्रबन्धों में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

विवरण

क्योंकि चावल का थोक व्यापार लेने की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए न केवल कार्यचालन सम्बन्धी ब्यौरों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी बल्कि राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों के पूर्ण योगदान और सहयोग की भी आवश्यकता थी, इसलिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्रियों / राज्यपालों और विरोधी दलों के नेताओं से कई एक बार विचार विमर्श किया। इन बैठकों में इस योजना में आने वाली कई कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। बफर स्टाक और अपेक्षित प्रबन्ध न होने के कारण आगामी खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने से सम्बन्धित नीति का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता थी।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और चावल की अधिप्राप्ति में पर्याप्त तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए, उचित यही समझा गया कि यह बात राज्यों पर छोड़ दी जाए कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिप्राप्ति की कोई भी प्रणाली अपना लें। तथापि, मोटे तौर पर राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि वे या तो उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाने अथवा मिल मालिकों / व्यापारियों पर लेवी लगाने की प्रणाली को अथवा दोनों प्रणालियों को अपनाएं और भारी संख्या में हुलरों को भी अपने नियंत्रण और देख-रेख में लाए। जो राज्य सरकारें 1973-74 के खरीफ के मौसम से चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के इच्छुक थे उनको ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तदनुसार, असम राज्य सरकार ने पहली नवम्बर, 1973 से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया है।

Indo-U.S.S.R. Wheat Loan Agreement

*7. SHRI VIRBHADRA SINGH:
SHRI S. M. BANERJEE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

() whether the Indo-U S.S.R. wheat loan Agreement was signed in October, 1973; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OFN AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b). The broad features of the Agreement signed with USSR Government pertaining to its offer of a loan of 2 million tonnes of foodgrains are as follows:—

(i) The entire quantity of foodgrains will be in the shape of wheat;

(ii) Of the total quantity of 2 million tonnes of wheat the various sources would be as follows:—

Russia	—10.5 lakh tonnes
Canada	— 4.5 lakh tonnes
Australia	— 5.0 lakh tonnes

(iii) Immediately India will bear the cost of transporting 10.5 lakh tonnes of wheat from the Soviet Union and 5 lakh tonnes of wheat from Australia. The Soviet Union will bear the cost of transporting 4.5 lakh tonnes of wheat to be supplied from Canada.